EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

TRAI's decision to delay the implementation of NTO 2.0 till April 2022 should give the stakeholders time to prepare themselves and assess the mood. The Govt is also extending a helping hand and trying to resolve issues with an open mind. The new TRAI chairman and the new I&B Secretary under the new I&B minister are adopting a more accommodating stance to help clear some of the mess. The Supreme Court has adjourned the NTO 2.0 matter to February 15, 2022. The matter pertains to the petitions filed by broadcasters against the Bombay High Court order over the implementation of NTO 2.0, issued by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

The year 2021 in review was a tumultuous one and saw the industry record some major announcements. The Zee-Sony merger was one of them. This is still an ongoing battle between them and as things stand currently should see things swing Zee's way in favour of the merger.

The Government's telecom reforms have given a new lease of life to the telecom companies. More action has been seen on the satellite broadband segment, with major players seeking to enter the business in India. Starlink, the broadband internet system of the Elon Musk-founded SpaceX, is not licensed to offer satellite-based internet services in India, the Govt announced recently and also advised the public to not subscribe to the services offered by the company, which are available for pre-booking. The government said that the company has started pre-selling or booking of their satellite based Starlink Internet Services in India. After taking the flak for its action Starlink Internet Services has applied for a licence to begin pilot services.

However the future for MSOs and LCOs is to take advantage of their last mile rural and urban connectivity and bundle OTT and broadband services and become resellers. They can realise the market size of 40 to 50 million audience. India as a market offers an excellent potential with a size of 170 to 180 million Pay TV and can reach 80 million broadband in three years. This is the belief of Saurabh Sancheti, CFO of Jio Platfroms, and one who created the success story of Reliance's Cable business post its acquisition of two largest cable TV and broadband companies in the country - Hathway Cable & Datacom and DEN Networks for a sum of Rs 5,230 crore in 2018.

So, in the coming new year – 2022, the LCO and MSO community can fine-tune and realign their strategy for growth.

(Manoj Kumar Madhavan)

*अप्रैल **2022** तक एनटीओ **2.0** के कार्यान्वयन में देरी करने के ट्राई के फैसले से हितधारकों को खुद को तैयार करने और मूड का आकालन करने का समय मिलना चाहिए। सरकार भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है और खुले दिमाग से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ट्राई के नये अध्यक्ष और आईएंडबी मंत्रालय के तहत नये आईएंडबी सचिव, कुछ गड़बड़ियों को दूर करने में मदद करने के लिए अधिक मिलनसार रूख अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीओ **2.0** मामले को **15** फरवरी **2022** तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी एनटीओ **2.0** के कार्या न्वयन पर वांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रसारकों द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है।*

*समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष **2021** एक उथल-पुथल वाला था और उद्योग ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं को रिकॉर्ड करते हुए देखा। जी-सोनी का विलय उनमें से ही एक था। यह लड़ाई अभी भी जारी है और जैसाकि वर्तमान में मामला का मौजूदा रूख है तो यह रूख विलय के पक्ष में जी के रास्ते में झूलती हुई नजर आयेगी।*

सरकार के दूरसंचार सुधारों ने दूरसंचार कंपनियों को नया जीवन दिया है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड खंड पर अधिक हलचल देखने को मिल रही है जिसके तहत कई प्रमुख खिलाड़ी भारत में कारोवार में प्रवेश करना चाहते हैं। स्टारलिंक, एलोन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स की ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रणाली, भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है और जनता को कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सदस्यता नहीं लेने की सलाह दी है, जो प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि कंपनी ने भारत में अपने सैटेलाइट आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की प्री सेलिंग या बुकिंग शुरू कर दी है। अपनी कार्रवाई के लिए आलोचना झेलने के वाद स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं ने पायलट सेवायें शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

*हालांकि एमएसओ और एलसीओ के लिए भविष्य, उनकी ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी का लाभ उठाना और ओटीटी व ब्रॉडबैंड सेवाओं को वंडल करना और पुर्नविक्रता वनना है। वे **40** से **50** मिलियन दर्शकों के वाजार के आकार का एहसास कर सकते हैं। एक वाजार के रूप में भारत **170** से **180** मिलियन पे टीवी के आकार के साथ एक उत्कृष्ट क्षमता प्रदान करता है और तीन वर्षों में **80** मिलियन ब्रॉडबैंड तक पहुंच सकता है। यह जियो प्लेटफॉर्म के सीएफओ सौरभ संचेती का विश्वास है और जिसने **2018** में **5230** करोड़ रुपये की राशि के साथ देश में दो सबसे वड़ी केवल टीवी और ब्रॉडबैंड कंपनियों हैथवे केवल एंड डेटाकॉम और डेन नेटवर्क के अधिग्रहण के वाद रिलायंस के केवल व्यवसाय की सफलता की कहानी वनायी।*

*इसलिए आने वाले नये साल-**2022** में एलसीओ और एमएसओ समुदाय, विकास के लिए अपनी रणनीति को वेहतर वना सकते हैं और उसे साकार कर सकते हैं।*

(Manoj Kumar Madhavan)